(ख) यदि हां, तो कितने वैज्ञानिकों ने गत तीन वर्षों में इन संस्थानों को छोड़ा है और उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इस बात के लिए क्या विशेष कदम उठाये जा रहे हैं कि वैज्ञानिकों के बीच असन्तोष का वातावरण न फैले और वे अपने अपने क्षेत्र में उत्साह पूर्वक अपना अपना योगदान दें ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख) गत तीन वर्षों में हारकोर्ट बटलर प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, कानपुर के क्रमशः 15 और 27 अध्यापकों ने इन संस्थानों को छोड़ा है। इनमें से अधिकांश लोगों ने इन संस्थानों को भारत के ही अन्य विश्वविद्यालयों/संस्थानों में उच्च पद प्राप्त करने के लिए छोड़ा है।

(ग) अध्यापकों के वेतनमानों और सेवा शर्तों तथा अनुसंधान सम्बन्धित अवसरों और सुविधाओं में भी हाल के वर्षों में पर्याप्त सुधार हुआ है। आज, अच्छे वैज्ञानिकों को अपनी विशेष भूमिकाएं निभानें के लिए भारत में ही पर्याप्त चुनौतीपूर्ण कार्य उपलब्ध हैं। यह तथ्य कि अध्यापकों/वैज्ञानिको का एक संस्थान को छोड़ कर अन्य संस्थाओं में अच्छे पद प्राप्त करने के लिए जाना एक अच्छा कदम है जिसे प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

Imposition of Levy on Khandsari Producing Units

1998. SHRI B. V. DESAI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that 3 States producing Khandsari have agreed to impose a levy on Khandsari production in their States;

(b) if so, whether other States have also decided to follow suit;

(c) if so, whether the quantum of levy has been decided by the Central Government;

(d) whether it will be done only after the States had made their recommendations to the Centre in this regard; and

(e) by what time Government is expected to take final decision of the quantum of levy?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) to (e). The Governments of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh have already imposed, with the concurrence of the Central Government, a 50 per cent levy on Khandsari produced by the first sulphitation process. The Governments of Andhra Pradesh and Karnataka have sent proposals for imposition of the levy to a lesser extent and these are under examination. The proposals of other States will be examined as and when received.

Land developed in Delhi under the Master Plan

1999. SHRI NIREN GHOSH: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether the Master Plan for 1961—80 in Delhi envisaged the development of 30,000 acres of land for residential purposes;

(b) if so, how much has been developed so far;

(c) whether the allegation that only 15,600 acres were being developed is correct;

(d) how many of the total 139 Zonal Development Plans have been acted upon;